IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)

बिहार शोध समागम BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 1, January-March, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

ISSN : 3048-6971

# बिहार राज्य में बालिका शिक्षा की स्थिति, नीति और प्रभाव का बालकों के संदर्भ में एक तुलनात्मक विश्लेषण (2005 - 2025)

**जयनाथ चौधरी**
**पीएच.डी. शोधार्थी**
**शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय**
**jnch251290@gmail.com**

https://doi.org/10.5281/zenodo.19372647

**सारांश (Abstract)**

यह शोध पत्र वर्ष 2005 से 2025 तक के दो दशकों में बिहार राज्य में बालिका शिक्षा (विशेषकर कक्षा 6 से 10) की स्थिति, सरकारी नीतियों और उनकी ज़मीनी हकीकत का बालकों के संदर्भ में एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करने वाले बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में बालिका शिक्षा में एक अनपेक्षित (Unexpected) मात्रात्मक वृद्धि देखी है। UDISE+, ASER, और आर्थिक सर्वेक्षण जैसे प्रमुख सांख्यिकीय दस्तावेजों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 1.0 को पार कर गया है, जो लड़कों की तुलना में लड़कियों के अधिक नामांकन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

इस जनसांख्यिकीय बदलाव और सफलता के पीछे सरकार की 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना', 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' और 'पोशाक योजना' जैसी सशर्त नकद हस्तांतरण और प्रोत्साहन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने बालिकाओं को हाशिये से निकालकर स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया है। हालाँकि, यह शोध पत्र स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि सरकारी नीतियों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक गहरा असंवाद (Divergence) मौजूद है। रजिस्टरों में नामांकन तो बढ़ा है, लेकिन कक्षाओं में वास्तविक उपस्थिति, बुनियादी ढाँचा (जैसे - क्रियाशील शौचालय और डिजिटल पहुंच) और सीखने के स्तर (Learning Outcomes) अभी भी अत्यधिक चिंताजनक हैं। बुनियादी गणित और डिजिटल कौशल में लड़कियाँ लड़कों से काफी पीछे हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय कुप्रबंधन और निधियों के कम उपयोग की चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। अंततः, यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि बिहार ने लैंगिक समानता में 'मात्रात्मक' सफलता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन बालिकाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए अब ''नामांकन'' से आगे बढ़कर शिक्षा की ''गुणवत्ता'' और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।

**मुख्य शब्द (Keywords):** बालिका शिक्षा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI), प्रोत्साहन योजनाएँ, ड्रॉपआउट दर, समावेशी शिक्षा।

## 1. परिचय (Introduction)

बिहार में शिक्षा का इतिहास विरोधाभासों से भरा रहा है। प्राचीन काल में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की भूमि रहा यह राज्य, आधुनिक काल के उत्तरार्ध में, विशेषकर 1990 के दशक में, शैक्षिक सूचकांकों पर देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाने लगा। वर्ष 2005 बिहार के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक 'विभाजक रेखा' (Watershed Moment) मानी जाती है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही, राज्य ने न्याय के साथ विकास के अपने आदर्श वाक्य के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को अपनी नीति के केंद्र में रखा।

यह शोध अध्ययन 2005 से 2025 तक के दो दशकों की शैक्षिक यात्रा का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस अवधि को बिहार में ''बालिका शिक्षा के पुनर्जागरण'' के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ 2005 में 'स्कूल से बाहर बच्चों' (Out of School Children - OoSC) की संख्या में बिहार देश में शीर्ष पर था, वहीं 2024-25 तक आते-आते राज्य ने नामांकन (Enrollment) के मामले में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हालाँकि, यह शोध केवल नामांकन के आँकड़ों तक सीमित नहीं है। यह अध्ययन सरकारी दस्तावेजों (UDISE+, PAB Minutes, CAG Reports), स्वतंत्र सर्वेक्षणों (ASER), और अकादमिक शोध पत्रों के माध्यम से यह जाँचती है कि क्या सांख्यिकीय वृद्धि ने बालिकाओं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किया है? क्या स्कूल जाने वाली लड़कियों की बढ़ती भीड़ वास्तव में सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है, या यह केवल 'कल्याणकारी योजनाओं' (Welfare Schemes) के वितरण का परिणाम है? इस शोध पत्र में जेंडर बजटिंग, समावेशी शिक्षा, और हाशिये पर खड़े समुदायों (विशेषकर महादलित और

अल्पसंख्यक) की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है।

## 2. शोध प्रविधि (Methodology) व शोध के प्रकार

### 2.1 शोध के प्रकार (Type of Research)

यह अध्ययन मुख्य रूप से वर्णनात्मक (Descriptive) और अन्वेषणात्मक (Exploratory) प्रकृति का है। इस शोध में मिश्रित शोध दृष्टिकोण (Mixed-methods approach) को अपनाया गया है, जिसमें सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मात्रात्मक (Quantitative) और ज़मीनी हकीकत व सामाजिक प्रभाव को गहराई से समझने के लिए गुणात्मक (Qualitative) दोनों प्रकार के विश्लेषण शामिल हैं। वर्णनात्मक शोध का उपयोग बालिका शिक्षा के बदलते रुझानों, सांख्यिकीय विशेषताओं और जनसांख्यिकीय बदलावों को दर्शाने के लिए किया गया है, जबकि अन्वेषणात्मक शोध का उपयोग यह जाँचने के लिए किया गया है कि नीतियाँ समाज में किस प्रकार काम कर रही हैं और उनके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

### 2.2 शोध प्रविधि एवं स्रोत (Methodology)

इस शोध के लिए आवश्यक जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) से प्राप्त की गई है। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 2005 से 2025 तक के निम्नलिखित प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और डेटाबेस का गहन विश्लेषण किया गया है:

- **सांख्यिकीय डेटाबेस:** राज्य में नामांकन दर, ड्रॉपआउट दर, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) के विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण के लिए UDISE+ तथा NITI Aayog के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index - PGI 2.0) के अद्यतन आँकड़ों का उपयोग किया गया है।
- **सीखने के प्रतिफल का मूल्यांकन:** ग्रामीण बिहार में बालकों व बालिकाओं के बीच बुनियादी शिक्षा, पठन क्षमता और गणितीय कौशल में मौजूद गुणात्मक अंतर का आकलन करने हेतु ASER (Annual Status of Education Report) रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है।
- **सरकारी नीतियाँ और वित्तीय दस्तावेज़:** बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25), जेंडर बजटिंग रिपोर्ट, और समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) के PAB Minutes का उपयोग राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं (यथा- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल और कन्या उत्थान योजना), वित्तीय प्रबंधन और बजट आवंटन की दिशा को समझने के लिए किया गया है।
- **अकादमिक और स्वतंत्र शोध:** विभिन्न स्वतंत्र अकादमिक शोध पत्रों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों का विश्लेषण कर सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच के असंवाद (Divergence) को स्थापित किया गया है।

**2.3 शोध सीमाएँ:** यह शोध पत्र उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) पर आधारित है और UDISE+ डेटा स्व-घोषित होती है, इसलिए इसमें अतिरंजना की संभावना हो सकती है।

## 3. बिहार राज्य में बालिका शिक्षा (कक्षा 6 से 10): सांख्यिकीय परिदृश्य का विश्लेषण

बिहार में बालिका शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए, हमें केवल निरपेक्ष संख्याओं को नहीं, बल्कि रुझानों (Trends), अनुपातों (Ratios), और तुलनात्मक आँकड़ों को देखना होगा। 2005 से 2025 के बीच के आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं - जहाँ पहुँच (Access) में क्रांति आई है, वहीं सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) और बुनियादी ढांचा (Infrastructure) चिंता का विषय बने हुए हैं।

### 3.1 नामांकन में वृद्धि और जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) की अभिव्यक्ति

पिछले दो दशकों में बिहार की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी उपलब्धि माध्यमिक स्तर पर लैंगिक अंतराल (Gender Gap) को पाटना रही है।

- **जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI):** UDISE+ 2021-22 और 2022-23 के आँकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में माध्यमिक स्तर पर GPI 1.0 को पार कर गया है, और यह लगभग 1.05 के स्तर पर स्थिर है (GMR Josephine et al., 2025)।

अकादमिक रूप से इसका अर्थ है कि अब माध्यमिक कक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन अधिक हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि 2005 में यह सूचकांक 0.8 से भी नीचे था।

- **नामांकन दर:** बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, 2024 में स्कूली शिक्षा शुरू करने वाली हर 100 लड़कियों में से 80 से अधिक ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जबकि 2019 में यह आँकड़ा केवल 73.5 था (Wani & Radhakrishnan, 2025)। यह दर्शाता है कि ठहराव (Retention) में सुधार हुआ है।

**तालिका – 1 : वर्ष 2024 में बालक और बालिकाओं के माध्यमिक शिक्षा पूर्णता व नामांकन रुझान**

| संकेतक | बालक (Boys) - 2024 | बालिका (Girls) - 2024 | विश्लेषण/रुझान |
|---|---|---|---|
| माध्यमिक शिक्षा पूर्णता | 77.2 (प्रति 100) | >80 (प्रति 100) | लड़कियों की पूर्णता दर लड़कों से बेहतर हो गई है (Wani & Radhakrishnan, 2025)। |
| नामांकन प्रवृत्ति | निजी स्कूलों की ओर पलायन | सरकारी स्कूलों में उच्च निर्भरता | लड़के निजी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में 'बालिकाकरण' (Feminization) हो रहा है (UDISE+, 2023 - 24)। |

### 3.2 ड्रॉपआउट दर: गिरते आँकड़े और छिपी चुनौतियाँ

ड्रॉपआउट दर शिक्षा प्रणाली की दक्षता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। 2005 के आसपास बिहार में ड्रॉपआउट दर खतरनाक रूप से उच्च थी, विशेषकर लड़कियों के लिए जो यौवन (Puberty) की आयु में पहुँचती थीं।

- **वर्तमान स्थिति:** UDISE+ 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 6.9% रह गई है (TOI, 2025)। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिक (1.9%) और उच्च प्राथमिक (5.2%) स्तर पर गिरावट देखी गई है, जिसका प्रभाव बिहार में भी परिलक्षित होता है (Economic Survey, 2024 - 25)।
- **आयु-विशिष्ट विश्लेषण (ASER 2023):** हालाँकि समग्र ड्रॉपआउट कम हुआ है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ बहिष्करण बढ़ता है। 14 वर्ष की आयु में केवल 3.9% लड़कियाँ स्कूल से बाहर होती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक (कक्षा 11-12 या उसके बाद) यह

आँकड़ा बढ़कर 32.6% हो जाता है (India Tomorrow, 2024)। यह इंगित करता है कि 10वीं कक्षा के बाद या विवाह योग्य आयु (18 वर्ष) के करीब पहुँचते ही लड़कियों को शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया जाता है।

### 3.3 साक्षरता दर में धीमी प्रगति

नामांकन में भारी वृद्धि के बावजूद, साक्षरता दर में वृद्धि की गति अपेक्षा से कम रही है।

- PLFS (Periodic Labour Force Survey) 2023-24 के आँकड़ों का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने चिंता जताई है कि बिहार की कुल साक्षरता 74.3% है। इसमें पुरुष साक्षरता 82.3% है, जबकि महिला साक्षरता 66.1% है (Abhinaya Harigovind, 2025)।
- 2011 की जनगणना (51.5%) की तुलना में यह लगभग 15 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है, लेकिन 66.1% का आँकड़ा अभी भी राष्ट्रीय महिला साक्षरता औसत (74.6%) से काफी नीचे है। लगभग 1.32 करोड़ महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं, जो वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है (Abhinaya Harigovind, 2025)।

### 3.4 डिजिटल और संज्ञानात्मक विभाजन (Cognitive Divide)

आँकड़ों की सबसे चिंताजनक परत सीखने के स्तर और डिजिटल पहुंच में है। ASER 2023 'Beyond Basics' रिपोर्ट (ग्रामीण बिहार, 14-18 आयु वर्ग), तालिका – 2 एक स्पष्ट गुणवत्ता संकट की ओर इशारा करती है।

**तालिका – 2 : 'Beyond Basics' रिपोर्ट (ग्रामीण बिहार, 14-18 आयु वर्ग) के आधार पर बालक और बालिकाओं का प्रदर्शन**

| कौशल क्षेत्र | बालक (प्रदर्शन) | बालिका (प्रदर्शन) | अकादमिक निष्कर्ष |
|---|---|---|---|
| **अंकगणित (भाग करना)** | 50% सक्षम | 37.8% सक्षम | बुनियादी गणित में लड़कियों का आधार कमजोर है (India Tomorrow, 2024; ASER, 2023)। |
| **अंग्रेजी पढ़ना** | 61.9% सक्षम | 54% सक्षम | भाषा कौशल में भी लड़के आगे हैं (India Tomorrow, 2024; ASER, 2023)। |
| **डिजिटल स्वामित्व** | 43.7% के पास अपना स्मार्टफोन | 19.8% के पास अपना स्मार्टफोन | लड़कों के पास सूचना तक पहुँचने के साधन दुगुने से अधिक हैं (India Tomorrow, 2024; ASER, 2023)। |
| **स्ट्रीम चयन (11वीं-12वीं)** | 36.3% STEM (विज्ञान) | 28.1% STEM | लड़कियाँ 'सॉफ्ट' विषयों (कला/मानविकी) की ओर धकेली जा रही हैं (ASER, 2023)। |

**सांख्यिकीय निष्कर्ष:** बिहार ने मात्रात्मक (Quantitative) रूप से लैंगिक समानता लगभग प्राप्त कर ली है, लेकिन गुणात्मक (Qualitative) रूप से एक गहरी खाई मौजूद है। लड़कियाँ स्कूल आ रही हैं, लेकिन वे लड़कों की तुलना में कम सीख रही हैं और आधुनिक तकनीक से वंचित हैं।

## 4. सरकार की समझ और नीतिगत हस्तक्षेप: समस्या का निदान और प्रोत्साहन योजनाएँ

बिहार सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, शिक्षा को केवल साक्षरता के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि प्रजनन दर नियंत्रण (Fertility Control) और सामाजिक सुधार के एक प्राथमिक उपकरण के रूप में देखती है। सरकार का यह स्पष्ट मत रहा है कि शिक्षित लड़की ही बाल विवाह, उच्च प्रजनन दर और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकती है।

### 4.1 समस्या की सरकारी परिभाषा (Problem Identification)

सरकार ने बालिका शिक्षा की बाधाओं को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया और उन्हें संबोधित किया:

1. **भौतिक बाधा (Physical Barrier):** घर से हाई स्कूल की दूरी।
2. **आर्थिक बाधा (Financial Barrier):** गरीबी के कारण पोशाक (Uniform), किताबें और फीस न दे पाना।
3. **ढाँचागत बाधा (Infrastructural Barrier):** स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सुरक्षा का अभाव।
4. **सामाजिक बाधा (Social Norms):** लड़कियों को पराया धन मानना और जल्दी शादी करना।

### 4.2 प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएँ: एक जीवन-चक्र दृष्टिकोण (Lifecycle Approach)

इन बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकार ने सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfer - CCT) और वस्तु-वितरण (In-kind transfer) का एक जटिल जाल बुना है।

#### 4.2.1 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (2006) - एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप

यह योजना बिहार ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर विकास अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय रही है।

- **प्रावधान:** कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए नकद राशि (वर्तमान में ₹3,500) दी जाती है (Prakash et al., 2025)।
- **प्रभाव:** इसने दूरी की लागत (Distance Cost) को कम किया है। अपने शोध अध्ययन में मुरलीधरन और प्रकाश, 2017 बताते हैं कि इस योजना ने माध्यमिक नामांकन में 32% की वृद्धि की और जेंडर गैप को 40% तक कम किया (Prakash et al., 2025)। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क पर साइकिल चलाती लड़कियों का समूह बिहार में महिला स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है।

#### 4.2.2 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY)

यह एक व्यापक योजना है जो जन्म से लेकर स्नातक तक बालिकाओं का समर्थन करती है।

- **शिक्षा-लिंक्ड प्रोत्साहन:** इंटरमीडिएट (12वीं) पास करने पर अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की राशि दी जाती है (*Bihar Budget Analysis 2021-22*)।
- **शर्त का महत्व:** 12वीं के लिए अविवाहित होने की शर्त ने बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन खड़ा किया है। यह योजना सीधे तौर पर प्रजनन दर और बाल विवाह को लक्षित करती है।

#### 4.2.3 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

- **उद्देश्य:** कपड़ों की कमी के कारण स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना।

- **राशि:** कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को ₹1,500 की राशि, और कक्षा 6-8 के लिए ₹1,000 की राशि DBT के माध्यम से दी जाती है (Bhattacharya, 2025)।

### 4.2.4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

- वंचित समूहों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक) की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। बिहार में 535 KGBV स्वीकृत हैं, जो उन लड़कियों के लिए अंतिम सहारा हैं जो सुदूर क्षेत्रों से आती हैं या ड्रॉपआउट हो चुकी हैं। यह योजना "समग्र शिक्षा अभियान" के तहत जेंडर इक्विटी का मुख्य स्तंभ है।

### 4.2.5 नीतिगत शिथिलता: 75% उपस्थिति नियम में बदलाव (2024-25)

- हाल ही में, 2025 के विधानसभा चुनावों और भीषण गर्मी की चुनौतियों को देखते हुए, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य 75% उपस्थिति के नियम को बंद करने का निर्णय लिया है (Bhattacharya, 2025)।
- **सरकारी तर्क:** सरकार का तर्क है कि इससे अधिक से अधिक लड़कियों को लाभ मिलेगा।
- **आलोचनात्मक विश्लेषण:** यह कदम लोकलुभावनवाद से प्रेरित प्रतीत होता है। उपस्थिति की शर्त हटाने से स्कूल केवल लाभ वितरण का केंद्र बन सकते हैं, जिससे नियमित कक्षा उपस्थिति और सीखने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

## 5. ज़मीनी हकीकत: क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और विरोधाभास

कागजों पर ये योजनाएँ अत्यंत सुगठित दिखती हैं, लेकिन 'शिक्षा मंत्रालय की PAB रिपोर्ट्स और CAG ऑडिट्स एक अलग और चिंताजनक वास्तविकता (Ground Reality) को उजागर करते हैं।

### 5.1 बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ: आँकड़ों का भ्रम

- **शौचालय:** UDISE+ 2023-24 रिपोर्ट दावा करती है कि बिहार के 97.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय क्रियाशील (Functional) हैं (Singh et al., 2025)। यह आँकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर दिखता है।
- **वास्तविकता:** हालाँकि, जमीनी रिपोर्टें और स्वतंत्र सर्वेक्षण अक्सर बताते हैं कि क्रियाशील की परिभाषा बहुत लचीली है। पानी की कमी, गंदगी और दरवाजों का टूटा होना आम समस्या है, जिससे लड़कियाँ मासिक धर्म के दौरान स्कूल आने से बचती हैं।
- **डिजिटल डिवाइड:** बिहार के केवल 25.2% स्कूलों (सरकारी और निजी संयुक्त) में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय औसत 64.7% के मुकाबले बहुत कम है। सरकारी स्कूलों में यह आँकड़ा मात्र 16.5% है (Udit Bubna, 2025)। PAB 2024-25 के मिनट्स में ICT और स्मार्ट क्लासरूम के प्रस्तावों की चर्चा और पिछले वर्षों में धन के कम उपयोग (low utilization) के कारण नए प्रस्तावों की अस्वीकृति यह दर्शाती है कि डिजिटल साक्षरता अभी भी एक दूर का सपना है (Bhawan et al., 2024)।

### 5.2 वित्तीय कुप्रबंधन और CAG रिपोर्ट के खुलासे

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की 2023 और 2024 की रिपोर्टें बिहार शिक्षा विभाग में गंभीर वित्तीय अनुशासनहीनता को उजागर करती हैं।

- **उपयोगिता प्रमाण पत्र (UCs) की पेंडेंसी:** 31 मार्च 2024 तक, बिहार सरकार ने ₹70,877 करोड़ से अधिक के UCs जमा नहीं किए थे, जिसमें शिक्षा विभाग का हिस्सा ₹12,623 करोड़ था (TOI News, 2025)। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार को यह प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि जारी किया गया पैसा वास्तव में लाभार्थियों (लड़कियों) पर खर्च हुआ या कहीं और।

- **फंड सरेंडर (Fund Surrender):** वर्ष 2022-23 में शिक्षा विभाग अपने कुल बजट का लगभग 25-30% हिस्सा खर्च ही नहीं कर पायी और राशि सरेंडर कर दी (CAG Report, 2024)। एक तरफ स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं हैं, दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये वापस किए जा रहे हैं। यह संसाधन की कमी नहीं, बल्कि क्रियान्वयन की क्षमता (Implementation Capacity) की कमी है।
- **DBT में देरी:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में अक्सर महीनों की देरी होती है। कई बार पोशाक की राशि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद मिलती है। जब पैसा समय पर नहीं मिलता, तो गरीब माता-पिता कर्ज लेकर पोशाक खरीदते हैं या बच्चों को बिना पोशाक भेजते हैं, जो शर्मिंदगी और ड्रॉपआउट का कारण बनता है।

### 5.3 शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता

- **शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR):** यद्यपि बिहार ने नए शिक्षकों की भारी भर्ती (BPSC के माध्यम से) की है, फिर भी UDISE+ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर PTR 54:1 और उच्च प्राथमिक पर 23:1 के आसपास है, जो आदर्श (30:1) से दूर है (Singh et al., 2025)।
- **महिला शिक्षक:** बिहार के सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन 2024-25 तक यह लगभग 43% के आसपास है, जो केरल (जहाँ यह बहुत अधिक है) जैसे राज्यों से कम है (Jadhav, 2025)। महिला शिक्षकों की उपस्थिति लड़कियों के नामांकन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

## 6. सरकारी प्रोत्साहन योजनाएँ और ज़मीनी हकीकत: संवाद व असंवाद (Convergence and Divergence) की स्थिति

क्या सरकारी योजनाएँ और ज़मीनी हकीकत आपस में संवादी है अर्थात बातचीत कर रही हैं या एक-दूसरे के विपरीत खड़ी हैं अर्थात असंवादी हैं?

### 6.1 संवादी क्षेत्र (Convergence) - जहाँ योजनाएँ सफल रहीं

1. **पहुँच और नामांकन:** साइकिल योजना और पोशाक योजना ने प्रवेश द्वार की बाधा को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। लड़कियों का स्कूल आना अब एक सामाजिक मानदंड (Social Norm) बन गया है। GPI > 1.0 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
2. **विवाह की उम्र में वृद्धि:** योजनाओं ने माता-पिता की मानसिकता को बदला है। इंटरमीडिएट पास करने पर मिलने वाली राशि के कारण परिवार अब शादी को कम से कम 18 वर्ष तक टालने के लिए तैयार हैं (Ghosh et al., 2020)।
3. **आकांक्षाओं का निर्माण:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) ने महादलित और अल्पसंख्यक लड़कियों में सपने देखने की क्षमता विकसित की है।

### 6.2 असंवादी क्षेत्र (Divergence) - जहाँ योजनाएँ विफल हो रही हैं

1. **नामांकन बनाम उपस्थिति (The Ghost Student Phenomenon):** सबसे बड़ा असंवाद यह है कि लड़कियाँ रजिस्टरों में मौजूद हैं, लेकिन कक्षाओं में नहीं। सरकारी स्कूलों में औसत उपस्थिति 50-60% से कम रहती है। 75% उपस्थिति नियम में ढील (Bhattacharya, 2025) इस समस्या को और गहरा करेगी। यह इंगित करता है कि शिक्षा प्रणाली 'ज्ञान' देने के बजाय 'वित्तीय लाभ' बांटने की मशीन बन गई है।

2. **प्रमाणपत्र बनाम कौशल:** कन्या उत्थान योजना डिग्री प्राप्त करने पर पैसा देती है, ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं। इसका परिणाम यह है कि परीक्षाओं में नक़ल और रटने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ASER 2023 का डेटा (जहाँ लड़कियाँ बुनियादी गणित में फेल हो रही हैं) इस बात का सबूत है कि हमारे पास 'स्नातक' तो हैं, लेकिन 'सक्षम युवा' नहीं (India Tomorrow, 2024)।
3. **डिजिटल वास्तविकता बनाम सरकारी दावे:** सरकार "स्मार्ट क्लास" और "डिजिटल बिहार" की बात करती है, लेकिन 80% लड़कियों के पास अपना फोन नहीं है, और केवल 16% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर हैं। यह नीति और वास्तविकता का सबसे बड़ा असंवाद है।

## 7. हाशियेकरण, बहिष्करण और समावेशन में योजनाओं की भूमिका

बिहार की सामाजिक संरचना (जाति, धर्म) शिक्षा में समावेशन को गहराई से प्रभावित करती है। 2023 की जाति जनगणना (Caste Survey) ने नीति निर्माण को नया आयाम दिया है।

### 7.1 समावेशन (Inclusion) में भूमिका

- **जातिगत समावेशन:** बिहार जाति जनगणना के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) राज्य की आबादी का 63% हैं (Singh, 2023)। साइकिल और पोशाक योजनाएं सार्वभौमिक (Universal) थीं, जिसने जातिगत बाधाओं को तोड़ा। एक दलित लड़की और एक सवर्ण लड़की का साथ-साथ साइकिल चलाकर स्कूल जाना सामाजिक समरसता का एक सशक्त दृश्य है।
- **अल्पसंख्यक लड़कियाँ:** PAB 2024-25 और अन्य रिपोर्टें दर्शाती हैं कि मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में सुधार हुआ है, हालांकि उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी अभी भी कम है (Zahid Maniyar, 2023)।

### 7.2 बहिष्करण (Exclusion) के नए स्वरूप

- **महादलित (मुसहर) समुदाय:** शोध (UNICEF 2025 रिपोर्ट) बताते हैं कि मुसहर समुदाय की लड़कियाँ अभी भी सबसे अधिक वंचित हैं। बाल श्रम और सामाजिक भेदभाव के कारण वे स्कूलों में नामांकित होकर भी बाहर हैं (Singh et al., 2025)।
- **डिजिटल बहिष्करण (Digital Exclusion):** जैसा कि ASER डेटा दिखाता है, लड़कियों के पास तकनीक की पहुँच कम है। यह उन्हें भविष्य के रोजगार बाजार और उच्च शिक्षा के अवसरों से बहिष्कृत कर रहा है।
- **विषय-आधारित बहिष्करण (Stream-based Exclusion):** लड़कियों को विज्ञान (STEM) के बजाय कला (Arts) विषयों में धकेला जा रहा है। UDISE+ और ASER डेटा बताते हैं कि 11वीं-12वीं में विज्ञान संकाय में लड़कों का वर्चस्व है। यह एक सूक्ष्म बहिष्करण है जो लड़कियों को उच्च वेतन वाली तकनीकी नौकरियों से दूर रखता है।

## 8. बालकों की शिक्षा से तुलनात्मक विश्लेषण: जेंडर गैप का बदलता स्वरूप

बिहार में बालिकाओं की शिक्षा की तुलना बालकों से करने पर एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जिसे तालिका – 3 में प्रदर्शित किया गया है, जिसके आधार पर हम इसे "मात्रात्मक समानता, गुणात्मक असमानता" कह सकते हैं।

**तालिका – 3 : बालकों और बालिकाओं की तुलनात्मक शैक्षिक स्थिति**

| तुलना का आधार | बालक (Boys) | बालिका (Girls) | विश्लेषण |
|---|---|---|---|
| नामांकन (माध्यमिक) | GPI < 1.0 (निजी | GPI > 1.0 (सरकारी | सरकारी स्कूल अब मुख्य रूप से लड़कियों और अति-गरीब लड़कों के लिए रह गए हैं। |

| तुलना का आधार | बालक (Boys) | बालिका (Girls) | विश्लेषण |
|---|---|---|---|
| | स्कूलों की ओर पलायन) | स्कूलों में बाहुल्य) | संपन्न परिवार लड़कों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं। |
| **सीखने का स्तर (बुनियादी)** | 50% लड़के भाग (Division) कर सकते हैं | 37.8% लड़कियाँ ही सक्षम हैं | समान कक्षा में होने के बावजूद, लड़कियों के सीखने का स्तर कम है, जो शायद घरेलू काम के बोझ और कम उम्मीदों का परिणाम है। |
| **डिजिटल कौशल** | 43.7% के पास अपना फोन, डिजिटल कार्यों में बेहतर | 19.8% के पास फोन, डिजिटल कार्यों में कमजोर | 21वीं सदी के कौशल में लड़के, लड़कियों से कोसों आगे हैं। |
| **श्रम बल भागीदारी** | 40.3% लड़के पढ़ाई के साथ काम करते हैं (खेत/दुकान) | अधिकांश लड़कियाँ घरेलू देखभाल (Care Economy) में लगी हैं | दोनों का समय बंटता है, लेकिन लड़कों का काम आर्थिक माना जाता है, और लड़कियों का कर्तव्य। |
| **भविष्य की दिशा** | तकनीकी शिक्षा, रोजगार, प्रवास | कला संकाय, विवाह, पारंपरिक भूमिकाएँ | शिक्षा प्रणाली जेंडर भूमिकाओं को तोड़ने में विफल रही है; इसने केवल शिक्षित गृहिणियाँ तैयार की हैं। |

**स्रोत : (India Tomorrow, 2024)**

## 9. निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

2005 से 2025 तक बिहार में बालिका शिक्षा की यात्रा "अंधकार से उजाले की ओर" तो है, लेकिन यह उजाला अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने 'इच्छाशक्ति' और 'धन' (बजट आवंटन) के माध्यम से एक ढाँचा खड़ा किया है, जिसने लड़कियों को घर से बाहर निकाला है और साइकिल योजना अपने आप में एक वैश्विक सफलता की कहानी है।

किंतु, वर्तमान स्थिति (2025) यह मांग करती है कि बिहार अब **नामांकन** से आगे बढ़कर **गुणवत्ता** की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाये।

1. **डेटा बनाम वास्तविकता:** सरकार को UDISE+ के आँकड़ों पर आत्ममुग्ध होने के बजाय ASER जैसे सर्वेक्षणों के द्वारा उजागर की गयी अधिगम की खाई को गंभीरता से लेना होगा। 75% उपस्थिति में ढील जैसे लोकलुभावन फैसलों को वापस लेकर सख्त शैक्षणिक अनुशासन लागू करना होगा।
2. **वित्तीय दक्षता:** CAG द्वारा इंगित ₹12,000 करोड़ से अधिक के फंड सरेंडर और UCs की पेंडेंसी को समाप्त करना होगा। प्रक्रियात्मक देरी को कम करके DBT को समयबद्ध बनाना होगा।

3. **डिजिटल समानता:** लड़कियों के लिए विशेष ''डिजिटल साक्षरता मिशन'' और ''मुफ्त डेटा/टैबलेट'' योजना की आवश्यकता है, ताकि वे लड़कों के बराबर खड़ी हो सकें।
4. **सामाजिक व्यवहार परिवर्तन:** नकद राशि देना आसान है, लेकिन समाज की सोच बदलना कठिन। शिक्षा विभाग को केवल 'कोषागार' नहीं, बल्कि 'समाज सुधारक' की भूमिका निभानी होगी, ताकि लड़कियाँ केवल 'पास' न हों, बल्कि 'सक्षम' बनें।

बिहार की बालिका शिक्षा की कहानी यह दिखाती है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति पहाड़ों को हिला सकती है अर्थात नामांकन बढ़ा सकती है, लेकिन एक सतत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए केवल राजनीति नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक क्रांति की विशेष आवश्यकता है।

## संदर्भ (References)


1. Abhinaya Harigovind. (2025, December 19). *India's "100% literacy by 2030" goal hits Bihar wall*. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/india/india-literacy-2030-goal-hits-bihar-wall-10427620/
2. Bhattacharya, A. (2025, April 2). *Bihar Govt relaxes 75% attendance for Uniform and Bicycle Schemes ahead of Assembly Elections 2025 - The CSR Journal*. The CSR Journal. https://thecsrjournal.in/bihar-govt-relaxes-75-percent-attendance-uniform-bicycle-schemes-assembly-elections-2025/
3. Bhawan, S., Delhi, N., To, E., Rajib, S., Sen, K., Adviser, S., Dinesh Saklani, A., Sudhanshu Bhushan, Singh, Y., Bhawan, H., & Marg, S. (2024). Subject: Samagra Shiksha -Minutes of the meeting of the Project Approval Board (PAB) held on 31't January, 2024 -Circulation of Minutes in respect of State of Maharashtra. In *Budget (AWP&B)* (pp. 2024–2049). https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/pab/PAB_MH_2024_25_compressed.pdf
4. *Bihar Budget Analysis 2021-22*. (2026, March 31). PRS Legislative Research. https://prsindia.org/budgets/states/bihar-budget-analysis-2021-22
5. CAG Report. (2024). *State Finances Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March 2023*. Government of Bihar *Report No. 01 of the year 2024.*
6. Economic Survey. (2024 - 25). *INDIA'S SCHOOL EDUCATION SYSTEM SERVES 24.8 CRORE STUDENTS ACROSS 14.72 LAKH SCHOOLS WITH 98 LAKH TEACHERS: ECONOMIC SURVEY 2024-25*. Pib.gov.in. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2097864&reg=3&lang=2
7. *GENDER BUDGET*. (2024 - 25). https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/gbdocuments/17107782611749468962.pdf
8. Ghosh, S., Singh, D., Joshi, M., & Priyadarshini, A. (2020). *Early Marriage in India with Special Reference to Bihar: An Evidence Review Sakshamaa: Initiative for What Works, Bihar Centre for Catalyzing Change*. https://www.c3india.org/uploads/news/Sakshamaa_Early_Marriage_Evidence_Brief_Aug2020.pdf
9. GMR Josephine, Tatta, A., Maruthi Anugandhula, & Sivasankar Mandal Baidya. (2025). Gender disparity in education and its impact on women empowerment in India. *International Journal of Psychology Research*, *7*(2), 115–119. https://doi.org/10.33545/26648903.2025.v7.i2b.102
10. India Tomorrow. (2024, January 23). *ASER 2023 uncovers alarming gaps in rural youth education, digital access, skills; experts suggest remedial measures - IndiaTomorrow*. IndiaTomorrow. https://indiatomorrow.net/2024/01/23/aser-2023-uncovers-alarming-gaps-in-rural-youth-education-digital-access-skills-experts-suggest-remedial-measures/
11. Jadhav, V. (2025, November 21). *A closer look at India's expanding teaching workforce | IDR*. India Development Review. https://idronline.org/article/education/a-closer-look-at-indias-expanding-teaching-workforce/
12. Kumari, Dr. N. (2025). The Role of Education in Reducing Gender Disparities in Bihar. *International Journal of Advances in Engineering and Management*, *7*(8), 817–821. https://doi.org/10.35629/5252-0708817821
13. Muralidharan, K., & Prakash, N. (2017). Cycling to School: Increasing Secondary School Enrollment for Girls in India. *American Economic Journal*: Applied Economics
14. Prakash, N., Pawar, S., & Pandey, V. (2025). *Pedalling towards gender equality and empowerment*. Ideasforindia.in. https://www.ideasforindia.in/topics/social-identity/pedalling-towards-gender-equality-and-empowerment
15. Singh, A. (2023, October 2). *Caste survey: OBC, EBC, SC, ST make up 85% of Bihar's population*. The Times of India; The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/india/caste-survey-obc-ebc-sc-st-make-up-85-of-bihars-population/articleshow/104113493.cms
16. Singh, R., Saberwal, R., Mukherjee, P., & Ubale, P. (2025). *What Drives Changes in Child Labour and Schooling? Evidence from an exploratory study among children of the Musahar community in Vaishali, Bihar, India,* Young Lives India and UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, New Delhi and Florence, May 2025.
17. TOI News. (2025, July 25). *CAG flags "embezzlement risk" in Bihar: Where is Rs 70,877 crore? Report says no assurance funds used for intended purpose*. The Times of India; The Times Of India. https://timesofindia.indiatimes.com/india/cag-flags-embezzlement-risk-in-bihar-where-is-rs-70877-crore-report-says-no-assurance-funds-used-for-intended-purpose/articleshow/122898571.cms

18. TOI. (2025, August 29). *Bihar betters pupil-teacher ratio*. The Times of India; The Times Of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/bihar-betters-pupil-teacher-ratio/articleshow/123585390.cms
19. UDISE+. (2023 - 24). *REPORT ON UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY 2*. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/udise_report_nep_23_24.pdf
20. Udit Bubna. (2025, August 29). *Govt report flags digital divide in schools—25% in Bihar, Bengal have computer facilities, 65% nationally*. ThePrint; theprint. https://theprint.in/india/education/govt-report-flags-digital-divide-in-schools-25-in-bihar-bengal-have-computer-facilities-65-nationally/2731591/
21. Wani, S., & Radhakrishnan, V. (2025, January 4). *School dropout rates go from bad to worse in Bihar and Assam*. The Hindu. https://www.thehindu.com/data/school-dropout-rates-go-from-bad-to-worse-in-bihar-and-assam/article69056787.ece
22. Zahid Maniyar. (2023, June 8). *Educational inequities worsen for Muslim students in India*. CJP. https://cjp.org.in/educational-inequities-worsen-for-muslim-students-in-india/